

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1072] No. 1072] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 31 मार्च. 2017

का.आ. 1212(अ).—1(i) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहन सहित) और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण का प्रसार करने के लिए 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान' का शुभारंभ करने हेतु तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद (एनसीईएम) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की दिनांक 31 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः-

1)	सचिव (भारी उद्योग विभाग)	-	अध्यक्ष
2)	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	-	सदस्य
3)	सचिव (राजस्व विभाग)	-	सदस्य
4)	सचिव (विद्युत मंत्रालय)	-	सदस्य
5)	सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)	-	सदस्य
6)	सचिव (शहरी विकास मंत्रालय)	-	सदस्य
7)	सचिव (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	-	सदस्य
8)	सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	-	सदस्य
9)	सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	-	सदस्य
10)	सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	-	सदस्य
2611	GI/2017 (1)		

2611 GI/2017 (1)

11)	सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	-	सदस्य
12)	सलाहकार (परिवहन), नीति आयोग	-	सदस्य
13)	अध्यक्ष, टेक्नीकल एडवाइजरी ग्रुप	-	सदस्य
14)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैट्रिप/अध्यक्ष, एनएबी (प्रस्तावित)	-	सदस्य
15)	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स (एसआईएएम)	-	सदस्य
16)	अध्यक्ष, ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एसीएमए)	-	सदस्य
17)	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ मैन्युफेक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी)	-	सदस्य
18)	अध्यक्ष, बैटरी मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन	-	सदस्य
19)	संयुक्त सचिव (प्रभारी ऑटोमोबाइल डिवीजन)	-	सदस्य सचिव
	नामिन सत्स्यः		

नामित सदस्य:

ऑटोमोबाइल उद्योग, शैक्षणिक संस्थान तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त 6 सदस्य -

- 20) श्री विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, सीएमडी, किर्लोस्कर सिस्टम्स लि.
- 21) श्री विनोद दाशारी, एमडी, अशोक लीलैंड
- 22) श्री पवन गोयनका, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा
- 23) श्री एस विजय आनन्द, सीईओ, अमारा राजा बेटरीज
- 24) सुश्री अन्नामलाई हेमलता, एमडी, एमपेयर व्हीकल्स लि.
- 25) श्री सुदर्शन वेनू संयुक्त एमडी टीवीएस मोटर्स
- (ii) अध्यक्ष, एनबीईएम, समय-समय पर, आवश्यकतानुसार, राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों से सदस्यों सहित अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित कर सकते हैं।
- (iii) सदस्यों का कार्यकाल: नामित सदस्यों का बोर्ड में कार्यकाल दो वर्ष की अवधि या सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा। यदि आवश्यक हो, तो इन सदस्यों को अतिरिक्त अवधि हेतु, पुन: नामित किया जा सकता है।
- 2. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड के प्रकार्य और शक्तियां:- इस बोर्ड के मुख्य प्रकार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:-
 - क) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संबंधी मिशन कार्यक्रम की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तथा रूपरेखा, इसके उद्देश्य, मात्रात्मक परिणाम तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका और दायित्वों की जांच, निरुपण और प्रस्ताव करना।
 - ख) देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और सरकारी नियामक कार्रवाई और संभावित रणनीति का प्रस्ताव रखना और उनकी संस्तुति करना।
 - ग) आवश्यक नियामक कार्रवाई, प्रोत्साहन और परियोजनाओं का प्रस्ताव रखना और विश्लेषण करना, नियामक कार्रवाई की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव करना तथा इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी/मंत्रालय की सिफारिश करना और इन नियामक कार्रवाई/ परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूपरेखा का प्रस्ताव करना।
 - घ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी विधान, अधिनियम या अधिसूचना लाने या वर्तमान विधान, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन करने के लिए जांच करना और राष्ट्रीय परिषद को प्रस्ताव देना।
 - ङ) एनसीईएम को परियोजनाओं, स्कीमों, अध्ययनों, नियामक कार्रवाई और पहलों का मूल्यांकन करना तथा इसके लिए आवश्यक वित्त की संस्तुति करना।

- च) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग अवसंरचना के मानकीकरण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाना।
- छ) विभिन्न स्टेकहोल्डर मंत्रालयों, उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित विचार-विमर्श करना, समन्वय करना और यदि कोई बाधा हो, तो उसे सुलझाना।
- ज) एनसीईएम के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना और विभिन्न मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डरों को निदेश देना।
- झ) एनसीईएम द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और इसकी अनुपालन रिपोर्ट देना।
- ञ) विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना और मतभेद, यदि कोई हो, तो उसे सुलझाना।
- ट) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रायोगिक परियोजनाओं की जांच, संस्तुति तथा पर्यवेक्षण और समीक्षा करना।
- ठ) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों और संभावित व्यवसाय मॉडलों की जांच और प्रस्ताव करना।
- ड) घरेलू उद्योग में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहयोग और मेल-जोल की संभावना का पता लगाना और सिफारिश करना, तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करना तथा विश्व के अग्रणी अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ संभावित समझौता की संभावनाओं का पता लगाना।
- ढ) विभिन्न परियोजनाओं, स्कीमों और नियामक कार्रवाई की प्रगति का प्रबोधन, समीक्षा और रिपोर्ट देना तथा मध्याविधक सुधार, यदि कोई है, के लिए एनसीईएम को प्रस्ताव देना। किसी विशिष्ट कार्यक्रम/स्कीम, यदि कोई है, के अंशत: या पूर्णत: संवर्धन, संशोधन और समापन की अनुशंसा करना।
- ण) बोर्ड यदि आवश्यक समझे, तो विभिन्न विशिष्ट पहलुओं की जांच के लिए उप समितियां भी बना सकता है।
- त) कोई अन्य भूमिका जो इसे दी गई है।
- 3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड उपर्युक्त प्रकार्यों के निवर्हन हेतु समय-समय पर बैठक करेगा तथा एनसीईएम को सहायता देगा।
- 4. नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) एनबीईएम के तकनीकी सलाहकार और सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- 5. यह एनसीईएम के गठन हेतु भारत के राजपत्र में दिनांक 27 मई, 2011 को प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना (फा.सं.12(89)/2009-एईआई) के अधिक्रमण में है।

[फा. सं. 6/01/2017-एनएबी (ऑटो)] विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1212(E).—1(i) In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 31st March 2011 for the launch of the "National Mission for Electric Mobility" and for setting up of National Council for Electric Mobility (NCEM) & National Board for Electric Mobility (NBEM) to propagate electric mobility and manufacture of electric vehicles (including hybrid vehicles) and their components, the Central Government hereby constitutes the "National Board for Electric Mobility (NBEM)" with the following members, namely –

(1) Secretary (Department of Heavy Industry)	-	Chairman
(2) Secretary (Department of Economic Affairs)	-	Member
(3) Secretary (Department of Revenue)	-	Member
(4) Secretary (Ministry of Power)	-	Member
(5) Secretary (Ministry of Road Transport and Highways)	-	Member
(6) Secretary (Ministry of Urban Development)	-	Member
(7) Secretary (Ministry of New & Renewable Energy)	-	Member
(8) Secretary (Ministry of Environment, Forests & Climate Change)	-	Member
(9) Secretary (Department of Industrial Policy & Promotion)	-	Member
(10) Secretary (Ministry of Petroleum and Natural Gas)	-	Member
(11) Secretary (Department of Science & Technology)	-	Member
(12) Adviser [Transport], NITI Aayog	-	Member
(13) Chairman, Technical Advisory Group	-	Member
(14) CEO, NATRIP/Chairman, NAB (Proposed)	-	Member
(15) President, Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)	-	Member
(16) President, Automobile Component Manufacturers Association of India [ACMA]	-	Member
(17) President, Society of Manufacturers of Electric Vehicles [SMEV]	-	Member
(18) President, Battery Manufactures Association	-	Member
(19) Joint Secretary [In-charge of Automobile Diviosn]	- N	Member Secretary

Nominated Members:

Six members of eminence and expertise from the area of automobile industry, academia and research and development –

- (20) Shri Vikram Shreekant Kirloskar, CMD, Kirloskar Systems Ltd.
- (21) Shri Vinod Dashari, MD, Ashok Leyland
- (22) Shri Pawan Goenka, Mahindra & Mahindra
- (23) Shri S Vijay Ananad, CEO, Amara Raja Batteries
- (24) Ms Annamalai Hemalatha, MD, Ampere Vehicles Ltd.
- (25) Shri Sudarshan Venu, Joint MD, TVS Motors
- (ii) The Chairman, NBEM may also co-opt additional members including members from the State Governments or Union Territories, as required, from time to time.
- (iii) **Tenure of members**: The nominated members will have tenure of two years on the Board, or until further Government order, whichever is earlier. These members can be re-nominated for additional terms, if needed.
- 2. **Functions and Power of National Board on Electric Mobility**: The main functions and powers of the Board shall include:
 - a) To examine, formulate and propose the short-term and long-term plan and contours of the mission program on electric mobility, its objectives, quantifiable outcomes and roles and responsibilities of the various stakeholders.
 - b) To propose and recommend policy guidelines and government interventions and possible strategies for promoting electric mobility and for encouraging manufacture of electric vehicles in the country.
 - c) To analyze and propose the key interventions, incentives and projects required, propose the prioritization of the interventions and recommend the nodal agency/ministry for its implementation and propose the short-term and long-term road map for these interventions/projects.
 - d) To examine and propose to the National Council the introduction of any legislation, act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting electric vehicles and their manufacturing in India.
 - e) To evaluate and recommend to the NCEM the projects, schemes, studies, interventions and initiatives and fund requirement for the same.

- f) To expedite the standardization of electric vehicle charging systems and charging infrastructure.
- g) To hold regular deliberations to ensure synergy amongst the efforts of the various stakeholders Ministries, industry, academia and research institutes. Co-ordinate and resolve bottlenecks, if any.
- h) To formulate strategies and give directions to various ministries and other stakeholders for implementing the decisions of the NCEM.
- i) To ensure and report compliance of action for the various decisions taken by NCEM.
- j) To Co-ordinate and resolve difference of opinion amongst various ministries, if any.
- k) To examine, recommend, monitor and review electric mobility related R&D projects and pilot projects.
- 1) To evaluate and propose various mechanisms and possible business models for popularizing electric mobility.
- m) To explore and recommend possible collaborations and tie-ups for technology acquisitions, obtaining technical experts and exploring possible agreements with leading R&D centres globally to facilitate availability of technology to the domestic industry.
- n) To monitor, review and report the progress of various projects, schemes and interventions and also suggest midcourse corrections, if any, to the NCEM. Recommend the additions, modifications and closure of parts and whole of any particular programme/scheme, if any.
- o) The Board may, as deemed fit, also constitute Sub-Committees for looking into the various specific aspects.
- p) Any other role that is assigned to it.
- 3. The National Board for Electric Mobility (NBEM) would meet periodically, to discharge the above functions and shall assist the NCEM.
- 4. National Automotive Board (NAB) would function as technical advisor and secretariat of the NBEM.
- 5. This is in supersession of earlier notification for constitution of NCEM (F.No. 12(89)/2009-AEI) published in the Gazette of India on 27^{th} May 2011.

[F. No. 6/01/2017-NAB (Auto)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 31 मार्च. 2017

का.आ. 1213(अ).—1(i) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहन सिहत) और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण का प्रसार करने के लिए 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान' का शुभारंभ करने हेतु तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद (एनसीईएम) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल की दिनांक 31 मार्च, 2011 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद (एनसीईएम) का गठन करती है. जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे नामतः-

(1)	मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय)	-	अध्यक्ष
(2)	मंत्री (ऊर्जा मंत्रालय)	-	सदस्य
(3)	मंत्री (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	-	सदस्य
(4)	मंत्री (शहरी विकास मंत्रालय)	-	सदस्य
(5)	मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)	-	सदस्य
(6)	मंत्री (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	-	सदस्य
(7)	उपाध्यक्ष, नीति आयोग	-	सदस्य

- (8) मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) सदस्य
- (9) राज्य मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
- (10) राज्य मंत्री (वित्त) सदस्य
- (11) मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) सदस्य
- (12) प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सदस्य
- (13) सचिव, भारी उद्योग विभाग सदस्य सचिव

मनोनीत सदस्यः

ऑटोमोबाइल उद्योग, शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र से प्रतिष्ठित और विशेषज्ञता प्राप्त पांच सदस्य निम्नवत हैं-

- (14) डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग
- (15) श्री पवन मुंजाल, हीरो मोटर्स लिमिटेड
- (16) श्री अतुल सोबती, सीएमडी, बीएचईएल
- (17) सुश्री सुलज्जा फ़िरोदिया, उपाध्यक्ष, काइनेटिक मोटर्स कंपनी लिमिटेड
- (18) श्री रवि पिशारोदी, टाटा मोटर्स
- (ii) अध्यक्ष, एनसीईएम राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्यों सहित समय-समय पर यथा आवश्यक अतिरिक्त सदस्यों का भी सहयोग ले सकते हैं।
- (iii) सदस्य का कार्यकालः परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष, अथवा सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा। इन सदस्यों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अविध के लिए पुनः मनोनीत किया जा सकता है।
- 2. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद के प्रकार्य और शक्तियां:** परिषद के प्रकार्य व शक्तियां निम्नानुसार होंगीः-
- (क) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन कार्यक्रम के लघु-आविधक तथा दीर्घ-आविधक उद्देश्यों, इसके मात्रात्मक परिणामों और उपलब्धियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को अंतिम रूप देना और उनका अनुमोदन करना।
- (ख) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए समग्रतः व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश, निधि आवश्यकता और संचालन संबंधी मॉडल व रणनीतियों पर विचार और अनुशंसा/अनुमोदन करना।
- (ग) प्रमुख नियामक कार्रवाइयों, परियोजनाओं और अपेक्षित प्रोत्साहनों का अनुमोदन करना, इन नियामक कार्रवाइयों, परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना/इनके कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी/मंत्रालय स्वीकृत करना और इन नियामक कार्रवाइयों/परियोजनाओं के लिए लघु-आविधक तथा दीर्घ-आविधक रूप-रेखा को अंतिम रूप देना।
- (घ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी विधान, अधिनियम, अधिसूचना पर विचार करना और सरकार से अनुशंसा करना अथवा किसी विद्यमान विधान, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन की अनुशंसा करना।
- (ङ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों पर विचार करना और सरकार से उनकी अनुशंसा करना और माध्यम तथा दीर्घ-आवधिक अपेक्षाओं को अंतिम रूप देना।
- (च) विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।

- (छ) मैकेनिज्म, सहयोग, व्यापार मॉडल और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, तकनीकी विशेषज्ञता के अधिग्रहण के लिए संभावित सरकारी प्रोत्साहन/नियामक कार्रवाइयों तथा घरेलू उद्योग को प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुसाध्य बनाने के लिए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ करार करने पर विचार करना और अनुमोदन करना।
- (ज) विभिन्न परियोजनाओं, स्कीमों और नियामक कार्रवाईयों का प्रबोधन, समीक्षा करना तथा किसी विशिष्ट कार्यक्रम/स्कीम, यदि कोई है, में आंशिक तथा समग्र रूप से मध्याविध सुधार, संयोजन और उसको बंद किया जाना।
- (झ) विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए अंतिम प्राधिकार एनसीईएम के पास होगा।
- (ञ) राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले और सीधे उनसे संबंधित मामलों पर उनके विचारों और सरोकारों का भी ध्यान रखा जाएगा।
- (ट) अन्य कोई भूमिका, जो इसे समनुदेशित की गई है।
- 3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड (एनबीईएम) उपर्युक्त प्रकार्यों के निर्वहन हेतु समय-समय पर बैठक करेगा। एनबीईएम, एनसीईएम को सहायता देगा।
- 4. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) एनसीईएम के तकनीकी सलाहकार और सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- 5. यह एनसीईएम के गठन हेतु भारत के राजपत्र में दिनांक 27, मई, 2011 को प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना (फा.सं.12(89)/2009-एईआई) के अधिक्रमण में है।

[फा. सं. 6/01/2017-एनएबी (ऑटो)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1213(E).—1(i) In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 31st March 2011 for the launch of the "National Mission for Electric Mobility" and for setting up of National Council for Electric Mobility (NCEM) & National Board for Electric Mobility (NBEM) to propagate electric mobility and manufacture of electric vehicles (including hybrid vehicles) and their components, the Central Government hereby constitutes the "National Council for Electric Mobility (NCEM)" with the following members, namely –

(1) Minister (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)	-	Chairman
(2) Minister (Ministry of Power)	-	Member
(3) Minister (Ministry of New & Renewable Energy)	-	Member
(4) Minister (Ministry of Urban Development)	-	Member
(5) Minister (Ministry of Road Transport and Highways)	-	Member
(6) Minister (Ministry of Petroleum & Natural Gas)	-	Member
(7) Vice Chairman, NITI Aayog	-	Member
(8) Minister (Department of Science & Technology)	-	Member
(9) Minister of State (Ministry of Environment, Forests & Climate Cha	inge)-	Member
(10) Minister of State (Finance)	-	Member
(11) Minister (Ministry of Commerce and Industry)	-	Member
(12) Principal Scientific Advisor to the Prime Minister	-	Member
(13) Secretary, Department of Heavy Industry	- Memb	er Secretary

Nominated Members:

Five members of eminence and expertise from the area of automobile industry, academia and research and development –

- (14) Dr. V. K. Saraswat, Member, NITI Aayog
- (15) Shri Pawan Munjal, Hero Motors Ltd.
- (16) Shri Atul Sobti, CMD, BHEL
- (17) Ms Sulajja Firodia, Vice Chairman, Kinetic Motors Company Ltd.
- (18) Shri Ravi Pisharodi, Tata Motors
- (ii) The Chairman, NCEM may also co-opt additional members including members from the State Governments or Union Territories, as required, from time to time.
- (iii) **Tenure of members**: The nominated members will have tenure of two years on the council, or until further Government order, whichever is earlier. These members can be re-nominated for additional terms, if needed.
- 2. **Functions and Power of National Council on Electric Mobility**: The functions and powers of the Council would be as under:-
- (a) To finalize and approve the short-term and long-term objectives of the mission program on electric mobility, its quantifiable outcomes and the milestones along with roles and responsibilities of the various stakeholders.
- (b) Consider and recommend/approve overall broad policy guidelines, fund requirements and governance models and strategies for promoting electric mobility and for encouraging manufacture of electric vehicles in the country.
- (c) To approve the key interventions, projects and incentives required, prioritize these interventions, projects. Approve the nodal agency/ministry for its implementation and finalize the short-term and long-term road map for these interventions/projects.
- (d) To consider and recommend to the government any legislation, act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting electric vehicles and their manufacturing in India.
- (e) To consider and recommend to the government the additional resources required for promoting EV and their manufacturing in India including finalizing the medium and long term resource requirements.
- (f) To synergize the efforts being made by various Ministries, industry, academia and research institutes.
- (g) To consider and approve mechanisms, collaboration, business models, and possible government incentives/interventions in funding for technology acquisition, acquisition of technical expertise and for entering into agreements with leading R & D centres globally to facilitate availability of technology to the domestic industry.
- (h) To monitor, review the various projects, schemes and interventions and propose the mid-course corrections, additions and closure of parts and whole of any particular programme/scheme if any.
- (i) The NCEM shall be the final authority to resolve the differences of opinion amongst various ministries, if any.
- (j) In the matters falling within the domain of State Governments/Local bodies and directly related to them, their views and concerns will also be taken into account.
- (k) Any other role that is assigned to it.
- 3. The National Council for Electric Mobility would meet periodically, to discharge the above functions. The NCEM will be assisted by the NBEM.
- 4. National Automotive Board (NAB) would function as technical advisor and secretariat of the NCEM.
- 5. This is in supersession of earlier notification for constitution of NCEM (F.No. 12(89)/2009-AEI) published in the Gazette of India on 27^{th} May 2011.

[F. No. 6/01/2017-NAB (Auto)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.